अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया में आकार लेगा आइटी पार्क व इनक्यूबेशन सेंटर

- परियोजना के लिए पीएसयू का गठन, कंसल्टेंसी के माध्यम से प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट भी बनेगी
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंसी चुनने का दिया गया जिम्मा
- इलेक्ट्रानिक्स निकेतन में होंगे यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान जैसी नामी संस्थाओं के कार्यालय

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उद्यम व उन्नत प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने लखनऊ में इंटीग्रेटेड आइटी पार्क व इनक्यूबेशन सेंटर परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू दी है। कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति के जरिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएसयू) का गठन किया जाएगा। आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने यह जिम्मा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को सौंपा है, जिसने कंसल्टेंसी फर्म के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया में 40 एकड़ क्षेत्र में आइटी पार्क, एसटीपीआइ पार्क, इनक्यूबेशन सेंटर, स्टेट डाटा सेंटर बनाने के साथ कई अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। परियोजना के लिए नियुक्त होने वाला पीएसयू खासतौर पर इंटीग्रेटेड आइटी पार्क व इनक्यूबेशन सेंटर परियोजना के विकास व निर्माण कार्यों की मानिटरिंग करेगी। साथ ही देश व दुनिया के बड़े निवेशकों को भी आकर्षित करने का रोडमैप तैयार करेगी। यहां इलेक्ट्रानिक्स निकेतन नाम से आधुनिक सुविधाओं वाली इमारत बनेगी, जिसमें आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग, यूपीडेस्को, सीईजी, यूपीएलसी व श्रीट्रान जैसी संस्थाओं के कार्यालय होंगे।

औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न नीतियों के तहत सौंपी प्रोत्साहन राशि

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : आइटी एवं आइटीईएस नीति-2022 के तहत सैमसंग, लावा, एचसीएल समेत पांच इकाइयों को 212.63 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वहीं, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के तहत अम्बुजा सीमेंट और जिंदल सोल्यूशन समेत सात कंपनियों को 66.66 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के तहत पारले एग्रो, बिड़ला कार्पोरेशन, मंगलम सीमेंट, बृंदावन एग्रो समेत 10 इकाइयों को 98.25 करोड़ रुपये प्रोत्साहन लाभ दिया गया जबकि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2012 के तहत आठ निवेश इकाइयों को 877.23 करोड़ रुपये और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत एक इकाई को 58.28 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन लाभ मिला। एकमुश्त पुनर्वास नीति-2015 के अंतर्गत भी इकाई को 20 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान गई।

कार्ययोजना को छह चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ के अलावा आइटी पार्क के लिए विभिन्न जगहों का चयन होगा। निर्माण प्रक्रिया के दौरान फील्ड स्टडी, कांसेप्ट डेवलपमेंट, आरएफपी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सुपरविजन, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन, थर्ड पार्टी फर्म्स की सिलेक्शन व मानिटरिंग, नालेज मैनेजमेंट प्रमोशन, मार्केटिंग प्रमोशन, इनवेस्टमेंट प्रमोशन व आउटरीच जैसी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।

दो लाख वर्ग फीट में बनेगा सबसे बड़ा इनक्यूबेशन सेंटर : प्रदेश के सबसे बड़े इनक्यूबेशन सेंटर का रास्ता साफ हो गया है। इनक्यूबेटर फैसिलिटी दो लाख वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जबकि 30 एकड़ में आइटी पार्क, दो से तीन एकड़ में एसटीपीआइ व इतने ही क्षेत्र में स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आडिटोरियम युक्त कंवेंशन सेंटर, 100 सीटर मीटिंग हाल, बोर्ड रूम, कामर्शियल व इंडस्ट्रियल वर्क स्पेसेस, आफिस, रेजिडेंशियल कांपलेक्स, पार्क व ग्रीन स्पेसेस, एटीएम मशीन इंस्टालेशन व कैफेटेरिया आदि का निर्माण किया जाएगा।